www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE — सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 112 | जौनपुर शनिवार, 06 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वृहद गीतोत्सव में जल्द शामिल होंगे : पवन कल्याण

आंध्र प्रदेश, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण यहां कृष्णा मठ में चल रहे वृहद गीतोत्सव के समापन समारोह में सात दिसंबर को शामिल होंगे। आयोजकों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुतिगे मठ के महंत सुगणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी के चतुर्थ विश्व गीता पर्याय के तहत पुतिगे मठ के तत्वावधान में महीने भर से चल रहे गीतोत्सव का सात दिसंबर को समापन होगा। समापन समारोह शाम चार बजे प्रस्तावित है। पुतिगे मठ के दीवान नागराजा आचार्य और मठ प्रशासन के सचिव प्रसन्न आचार्य ने यह घोषणा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति से समापन समारोह का महत्व बढ़ेगा। पिछले चार सप्ताह के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर्षित हुए हैं। आठ नवंबर को प्रारंभ हुए गीतोत्सव का उद्घाटन पेजावर श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ द्वारा किया गया था जिसमें भगवद् गीता को लेकर अध्यात्मिक, सांस्कृतिक और गीता पाठ संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

एनआईए ने हथियार तस्करी मामले में कई राज्यों में छापेमारी के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को हथियार एवं गोला–बारूद तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित तीन राज्यों में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनआईए की 22 टीम ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना जिलों में सात स्थानों, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 13 स्थानों और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दो स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में विभिन्न बोर के हथियार और गोला–बारूद, एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्जी और संदिग्ध पहचान दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तलाशी के बाद एनआईए ने पटना से शशि प्रकाश, शेखपुरा से रवि रंजन सिंह और कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को अवैध गोला–बारूद की तस्करी, बिक्री और खरीद में शामिल बड़े गिरोह में उनकी सक्रिय भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में एनआईए की जांच के अनुसार, साजिश के तहत गोला–बारूद की तस्करी हरियाणा से उत्तर प्रदेश में की जा रही थी, और फिर उसे बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जा रहा था। यह मामला इस वर्ष जुलाई में बिहार में शुरू हुआ था, जहां स्थानीय पुलिस ने कई हथियार और गोला–बारूद जब्त करने और बरामदगी के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

रूसी नागरिकों को मिलेगा 30 दिन का मुफ्त वीजा, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका शुक्रिया। बातचीत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नियमित तौर पर फोन पर बातचीत होती रहती है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सभी तरह के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार हैं। रूस भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में भी मदद कर रहा है। दोनों देश भुगतान के निराकरण के लिए धीरे–धीरे अपनी–अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के इस्तेमाल की ओर भी बढ़ रहे हैं। हम सालाना द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की आशा रखते हैं। भारत और यूरेशियन इकॉनोमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी बातचीत चल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, श्हम सबसे बड़ा भारतीय न्यूक्लियर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। छह में से तीन रिएक्टर पहले ही एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, श्पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण हमला, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा, श्दोनों देशों के बीच स्नेह और आत्म–सम्मान का भाव रहा है। हाल ही में रूस में भारत के दो नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम और आपस में नजदीकियां बढ़ेंगी। शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निरूशुल्क 30 दिन का टूरिस्ट वीजा और 30 दिन के ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। दोनों देशों के स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान–प्रदान बढ़ेगा।

योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान केंद्रित हो : शिवराज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नई दिल्ली के कृषि भवन में गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित थे। फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा और रणनीति निर्धारण– बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने एनएचबी की योजनाओं की समीक्षा की। विशेष रूप से वाणिज्यिक बागवानी विकास योजनाएं, कोल्ड–चेन अवसंरचना परियोजनाएं, क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी)– क्षेत्र–विशिष्ट बागवानी क्लस्टरों के माध्यम से उत्पादकता और बाजार जुड़ाव को बढ़ाने की नई पहल, क्लीन प्लांट कार्यक्रम–उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए रोग–मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा

हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान–केंद्रित हो तथा किसानों को सब्सिडी भी समय पर दी जाए, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से समान रूप से सभी राज्यों में हमारे छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचना चाहिए, उनकी आय बढ़नी चाहिए, और विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों के किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए। साथ ही, शिवराज सिंह ने किसानों के हित में जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के संबंध में विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़े, किसानों को नुकसान नहीं हो, और नुकसान से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएं। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक सुझाव दिए।

अमित शाह ने स्वदेशोत्सव 2025 का किया उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिला नया मंच

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय मैदान में श्स्वदेशोत्सव 2025श का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह राष्ट्रव्यापी एक्सपो 5 दिसंबर, 2025 से 9 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद, गृह मंत्री ने स्वदेशी की शक्ति का प्रतीक श्स्वानुभूति प्रदर्शनीश का भी अनावरण किया। इस स्वदेशी उत्सव के दौरान ज्ञान और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सेमिनार आयोजित किए गए हैं, ऐसा विज्ञप्ति में कहा गया है। तदनुसार, 5 दिसंबर को उद्घाटन दिवस पर पर्यावरण संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 6 दिसंबर को स्टार्टअप उड़ान 2025 और स्वदेशी संकल्प अभियान पर सत्र निर्धारित हैं। 7 दिसंबर के सत्र मातृशक्ति की भूमिका और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर केंद्रित होंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 दिसंबर को आयुर्वेद और स्वास्थ्य के साथ–साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सेमिनार होंगे। अंतिम दिन, 9 दिसंबर को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर चर्चा होगी । साथ ही, प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से रात 10रू00 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रहीं खेलकूद की गतिविधियां : योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों का आह्वान किया और कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की है कि वह किसी न किसी खेल के साथ अवश्य जुड़े, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे। सीएम ने कबड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि इस खेल में स्फूर्ति और व्यक्ति के मन में टीम भावना के साथ कार्य करने का जज्बा भी है। हर खेल व खेल संस्कृति टीम वर्क के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देती है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल व खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने रीजनल स्टेडियम में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज सप्तम् अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता–2025 के विजेताओं को पुरस्कृत किया। सीएम योगी ने कहा कि धर्म के जितने भी साधन हैं, उन सभी की पूर्ति स्वस्थ शरीर से ही संभव है। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है, जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष में सभी ने बदलते हुए भारत और पीएम मोदी की प्रेरणा से खेल व खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीयों के मन में जो भाव पैदा हुए हैं, उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपियन, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व चौंपियनशिप में अच्छा पुरस्कार ले रही हैं। खेल व प्रतियोगिताओं के प्रति नई जागरूकता पैदा हुई है। सांसद–विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अंदर पहले से तीन स्पोट्र्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर स्पोट्र्स कॉलेज होना चाहिए।

इंडिगो की 500 उड़ानें रद्द होने से आम लोग ही नहीं सांसद भी परेशान, राज्यसभा में उठा मुद्दा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इंडिगो ने पिछले दो दिनों में करीब 500 उड़ानों को रद्द किया है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को मुश्किलों को सामना करना पड़ा है। यह मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एयरलाइन के बढ़ते एकाधिकार का असर आम लोगों के साथ–साथ सांसदों पर भी पड़ रहा है। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, इसके कारण बड़ी संख्या में सांसदों की साप्ताहांत की यात्रा की योजनाओं पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया

कि कई संसद सदस्य आज घर जाने और सोमवार को वापस लौटने के लिए टिकट बुक कर चुके थे। लेकिन अब उड़ान रद्द होने से परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समस्या इंडिगो के एकाधिकार की वजह से पैदा हुई है। तिवारी ने सदन के जरिये पूछा कि जिस नियम के कारण यह स्थिति बनी है, उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक समस्या का समाधान होगा। उन्होंने मंत्री से सदन को जानकारी देने की मांग की। उनके सवाल पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सदन में आने से पहले ही उन्होंने विमानन मंत्री से बात की है और एयरलाइन की तकनीकी समस्याओं को देखा जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने विमानन मंत्री से आग्रह किया है कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब तैयार करें, क्योंकि कई सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की जानकारी सदन और आम नागरिकों दोनों को मिलनी चाहिए।

निर्मला सीतारमण पर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के बारे में राज्यसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उपनेता सागरिका घोष ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते समय पश्चिम बंगाल के बारे में सदन को "भ्रमित" किया। सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की पूरी सहायता के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास को नुकसान पहुंचाया है। वित्त मंत्री के जवाब के विरोध में सदन से बहिर्गमन करने के बाद संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए सागरिका ने इसे "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, "आज राज्यसभा में हमने संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या, संसदीय लोकतंत्र की हत्या देखी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के जवाब में माननीय वित्त मंत्री ने बार–बार बंगाल के बारे में सदन को भ्रमित किया, बार–बार बिना सबूत और बिना प्रमाण के बयान दिए।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में तृकां के नेता डेरेक ओ ब्रायन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, जिसके लिये उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सांसद महेश शर्मा की मां के निधन पर शोक जताया

उत्तराखंड, (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद डॉ. महेश शर्मा के नोएडा स्थित आवास पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक जताया। यह जानकारी स्थानीय सांसद के एक सहयोगी ने दी। गौतमबुद्धनगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा की मां ललिता शर्मा का 26 नवंबर को निधन हो गया था। सांसद के सहयोगी ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को शोक संतप्त परिवार से मिलने नोएडा के सेक्टर 15–ए स्थित शर्मा के आवास पहुंचे और उन्होंने लगभग आधे घंटे परिजनों के साथ समय बिताया। उनके मुताबिक, धामी ने डॉ. महेश शर्मा, उनकी पत्नी डॉ. उमा शर्मा तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना दी। धामी ने दिवंगत ललिता शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और पूर्व मंत्री अशोक कटारिया भी बृहस्पतिवार शाम शर्मा के आवास पहुंचे और परिवार को संवेदना व्यक्त की।

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ : मुर्मू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर दुख जताया और कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिवंगत दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति कौशल का बृहस्पतिवार दोपहर को निधन हो गया। वह 73 साल के थे। उन्होंने कहा, ''मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद और एक जाने–माने कानूनविद श्री स्वराज कौशल जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।'' मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मैं उनकी बेटी और सांसद बांसुरी स्वराज, परिवार के अन्य सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त

करती हूं।उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि ताल कटोरा रोड के उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की।वहीं इनके निधन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा– मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। स्वराज कौशल जी का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है। दु:ख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं सांसद बांसुरी स्वराज जी और उनके समस्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।

संपादकीय

अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है

विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच रुपया बुधवार को पहली बार 90 प्रति डॉलर के नीचे चला गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे टूटकर 90.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर था, लेकिन यह गिरावट यहीं नहीं थमी, बल्कि गुरुवार को एक डॉलर की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई। 2025 में रुपया 4 से 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में शामिल हो गया है। हालांकि यह दुख की बात है मोदी सरकार अपनी इस नाकामी को न मान रही है, न उसमें सुधार के लिए कोई काम करती दिख रही है। 11 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण रुपये की कीमत में सुधार आया हो। बल्कि लगातार गिरावट ही दर्ज होती रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन इस बार उनका ऐसा बेतुका तर्क भी सरकार का बचाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स तो स्थिर ही है। दरअसल भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों का घटता भरोसा रुपए की गिरावट का अहम कारण बन रहा है। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका में व्यापार समझौते पर अनिश्चितता कायम रहने और रुपये की गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक के आगे न आने से स्थानीय मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 3,642 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस वर्ष भारत ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में 16 से 18 अरब डॉलर की निकासी देखी, जबकि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास स्थिर रहा। यानी भारतीय बाजार से डॉलर अधिक निकले और निवेश कम हुए। इसके साथ ही, हर महीने वस्तु व्यापार घाटा 25–30 अरब डॉलर के बीच रहा। देश से पूंजी का बाहर जाना और आयात की मांग बढ़ना इन वजहों से रुपया कमजोर होता गया। गौरतलब है कि भारत तेल, कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है, वहीं, उच्च अमेरिकी ब्याज दरों से आकर्षित होकर वैश्विक निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इससे भी डॉलर की आवश्यकता बढ़ रही है, जबकि आने वाले डॉलर की आपूर्ति घट रही है। जब डॉलर की मांग रुपये की मांग से अधिक हो जाती है, तो रुपये का मूल्य गिरना तय है। ज्यादा आयात, धीमे निर्यात और अस्थिर पूंजी प्रवाह रुपये की गिरावट का मुख्य कारण हैं। और यह गिरावट अब महंगाई को बढ़ाएगी यह तय है। रुपए में गिरावट के साथ ही तेल और गैस कंपनियां, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक और केमिकल कंपनियों की लागत तुरंत बढ़ जाती है। आयातित खाद्य पदार्थ और दवाइयां भी महंगी हो जाती हैं। विदेश में शिक्षा और यात्रा भी परिवारों के लिए महंगी हो जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से कं ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और कार कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। इससे जीएसटी में कटौती के बाद इन क्षेत्रों में हुई अच्छी बिक्री का ट्रेंड पलट सकता है।

क्या भाजपा असम, और पश्चिमी बंगाल में जीत हासिल कर सकती है

अजय दीक्षित

असम और पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होने हैं। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के बिहार विधानसभा चुनावों में जीत के बाद दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि गंगा मैया बिहार से ही पश्चिमी बंगाल जाती है। प्रधानमंत्री का इशारा असम और पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों की ओर था । अभी दोनों राज्यों में से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है । 289 सदस्यीय पश्चिमी बंगाल विधानसभा में 289 सीट है। यहां पर 2021के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीट जीती थी। यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होगा ।जबकि असम में 117 सदस्यीय विधानसभा में चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। 2021 असम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 61 सीट जीती थी। कांग्रेस के तरुण गोगई और उनके पुत्र गौरव गोगई मरो करो का प्रश्न है। क्योंकि 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री है। दूसरी ओर चुनाव आयोग दोनों राज्यों में चुनाव से पहले मतदाता सूचियों गहन परीक्षण एसआईआर करा रहा है जिसके लिए ममता बनर्जी ने आंदोलन चला रखा है। बताया जाता है कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों में अब एक करोड़ बोटर कम हो जाएगा अभी 7.5 करोड़ लोग मतदाता सूचियों में दर्ज है ।असम में भी 50 लाख लोग मतदाता सूचियों में से हटाए जाने है। दोनों राज्यों में भारी संख्या में बंगला देश की घुसपैठी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राजद की करारी हार से पूर्वोत्तर भारत असर हुआ है । भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मोहाल बना है जिसका असर असम और पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा ।2021 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 39 फीसदी वोट मिला था और तृणमूल कांग्रेस से लगभग 61 लाख वोट कम मिला था जो लगभग 9 फीसदी अधिक था 289 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीट मिली थी ।जबकि तुड़मूल कांग्रेस को 212 सीट मिली। तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को मुद्दा बनाया था। इससे बंगाल अस्मिता का प्रश्न बनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपुला मानुष का मुद्दा उठाया। लोगों ने शायद इसी मुद्दे पर वोट डाले। अबकी बार स्थिति भिन्न है परसों दुर्गापुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का औद्योकरण,विकास,सड़क,

और तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है ।यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीत बदलते हुए बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। कहते हैं कि बंगाल में युवाओं का पलायन भी बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर हुआ है ।यानी रोजगार भी मुद्दा बनाया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल में अगर मछली उद्योग को छोड़ दें तो कोई बड़ा उद्योग नहीं है। कलकत्ता से कोलकाता बना शहर वस्त्र,पटसन, जुट, हैवी मास्नरी के जाना जाता था मगर अब मर गया है कोलकाता शहर ,शेष रह गई है तो बस यादें। पश्चिमी बंगाल इन दिन महिलाओं, स्त्रियां के शोषण के कुख्यात है और यहां से महिलाओं, स्त्रियां, बच्चियों की पूरे भारत में तस्करी होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के कोई योजना नहीं है ।दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल का सामाजिक तनावना बिगड़ रहा है और मुस्लिम बाहुल्य जिलों में अन्य हिन्दू, धर्म,जैन,परेशान हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण करन को बढ़ावा दे रही है।

चुप-चोरी आई श्रमिक संहिताओं के राज

अरविन्द

सबसे ज्यादा घालमेल न्यूनतम मजदूरी तय करने के मामले में किया गया है। छह कार्यस्थितियों में कौशल की चार श्रेणी के आधार पर कुल 24 न्यूनतम मजदूरी दर का हिसाब कौन मजदूर किस तरह रख पाएगा। यह इस सदी के श्रम आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल बनाना चाहिए। मजदूरों को मूल वेतन पर ज्यादा से ज्यादा पचास फीसदी भत्ते पाने का हद देकर यह संहिता अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन असल में मजदूरों के हाथ में कम पैसे मिलेंगे। मजदूरों से जुड़ी चार संहिताओं को आये आज लगभग दो सप्ताह (इनकी अधिसूचना 21 नवंबर को हुई थी) हो गए लेकिन कहीं से इस बारे में कोई खास उत्साह या विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऋण संस्थानों की लाइन को ब्रह्मवाक्य मानने वाले हमारे कुछ कथित अर्थशास्त्रियों ने इसे श्क्रांतिकारी कहा पर उस श्रेणी वाले ज्यादातर जानकार लोग भी इन्हें अपर्याप्त बताते नजर आए। विरोध और गलत बताने वाला स्वर तो और भी गायब है। यह देश में मजदूर आंदोलन की स्थिति से भी जुड़ा है क्योंकि अब देश में सबसे बड़ा मजदूर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ बन गया है। उसके एक नेता ने पिछले दस वर्षों में एक भी इंडियन लेबर कांफ्रेंस न होने का रोना तो रोया लेकिन संघ ने इन बदलावों का स्वागत कर दिया है। तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों ने इन संहिताओं को न लागू करने की घोषणा की है लेकिन वहां से भी आलोचना का कोई साफ स्वर नहीं सुना गया है। लेबर कांफ्रेंस ऐसा मंच है जिसमें मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि साझा रूप से कानूनी मामलों की चर्चा करते हैं। वैसे यह जानना भी जरूरी है कि जब छह साल पहले इन संहिताओं को संसद से पास किया गया था(उन्हीं दिनों खेती से जुड़े तीन विवादास्पद कानून भी ये थे) तब भी विपक्ष ने संसद का बहिष्कार किया था और ये संहिताएं बिना बहस के पास हुई थीं। अब यह संहिता शब्द आपको चुभ रहा होगा तो यह स्पष्टीकरण भी जरूरी है कि कानून या अधिनियम की जगह यह पद भी बहुत सोच समझकर लाया गया है। जिन 29 कानूनों को हटाकर इन चार संहिताओं को लाया गया है उनके खिलाफ विश्व बैंक और अंततरू मुद्रा कोष के लोग ही नहीं, देश में उदारीकरण के पैरवीकार भी काफी कुछ बोलते रहे हैं और इनको देश के औद्योगिक विकास में बाधक बताते रहे हैं। कानून में फेरबदल के लिए संसद या विधान सभाओं की मंजूरी जरूरी है और उसमें श्रमिकों के हितों की अनदेखी मुश्किल होती है। संहिता होते ही यह सुभीता हो गया है कि जिस सरकार को जरूरत लगे एक कार्यकारी आदेश से बदलाव कर सकती है। वैसे भी श्रम के समवर्ती सूची में होने के चलते इधर राज्य सरकारों ने पुराने कानूनों को हटाने और नए को लाने में पूरी उदारता बरती है। नई संहिताओं के अधिकांश बड़े प्रावधान राज्यों ने पहले ही लागू कर दिए हैं। लेकिन अब घोषित संहिताओं ने देश और दुनिया में चले लंबे श्रमिक आंदोलनों से हासिल कानूनी लाभों पर पूरा पानी फेर दिया है। यहां तक कि आठ घंटे काम करने के नियम को भी हाशिये पर ला दिया गया है। इन संहिताओं की सबसे चर्चित चीज कंपनियों के लिए मजदूरों की छंटनी करने और ठेके पर लेने के नियम आसान करना है। अब श्हायर एंड फायरश सहूलियत का लाभ लेने के लिए आपके यहां नियुक्त कर्मचारियों की संख्या सौ की जगह तीन सौ कर दी गई है। इससे देश की 90 फीसदी इकाइयां इस दायरे से बाहर चली गई हैं। और इसमें भी ठेका देने में 20 फीसदी का नियम ही नहीं खत्म किया गया है आपको एक ही काम और मजदूर को बार–बार ठेके पर रखने की छूट भी दे दी गई है। अब आप पचास फीसदी ठेका मजदूर रखकर काम करा सकते हैं। काम स्थायी प्रकृति का हो और मजदूर आपके उद्योग परिसर में ही काम करता हो तब भी ठेके पर रखने में कोई वैधानिक परेशानी नहीं है और अब इंस्पेक्टर नहीं रहे। उनकी जगह इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर आ जाएंगे जो आपकी

मदद ही करेंगे और बारह घंटे काम कराने में कोई कानूनी परेशानी नहीं है। जबकि आठ घंटे का नियम जाने कितने संघर्ष के बाद आया है। हम पत्रकारों के अपने कानून के हिसाब से तो साढ़े छह घंटे की ड्यूटी ही पर्याप्त थी जिसमें आधे घंटे का अवकाश भी होता था। सबसे ज्यादा घालमेल न्यूनतम मजदूरी तय करने के मामले में किया गया है। छह कार्यस्थितियों में कौशल की चार श्रेणी के आधार पर कुल 24 न्यूनतम मजदूरी दर का हिसाब कौन मजदूर किस तरह रख पाएगा। यह इस सदी के श्रम आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल बनाना चाहिए। मजदूरों को मूल वेतन पर ज्यादा से ज्यादा पचास फीसदी भत्ते पाने का हद देकर यह संहिता अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन असल में मजदूरों के हाथ में कम पैसे मिलेंगे। बाकी पैसा वेलफेअर के नाम पर कटेगा और वह कब और कैसे मिलेगा इसका हिसाब भी उतना ही जटिल है जितना न्यूनतम मजदूरी का। साफ दिखाता है कि पुरानी कानूनी सुरक्षा खत्म करने के बदले मजदूरों को कुछ लाभ दिलाने का जो दिखावा किया गया है उस कमाई का ज्यादातर हिस्सा सरकार के पास जाएगा जो मजदूरों तक पैसा पहुंचने के पहले उसका सदुपयोग करेगी। बिना बिजली वाली इकाई में अगर 40 लोग काम करते हों और बिजली वाली में 20 तो वह फैक्टरी की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। पहले यह सीमा क्रमशरू बीस और दस की थी। वे सब श्रम संहिता के दायरे से बाहर होंगे। अब बेसिक मजदूरी बढ़ाने से मजदूर खुश होंगे, सरकार का खजाना भरेगा लेकिन नियोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा जो अंततरू उत्पाद और उपभोक्ताओं पर ही जाएगा। उल्लेखनीय है कि आज ओलाध्उबर और आनलाइन मार्केटिंग के हंगामे में जो करोड़ों गिग और प्लेटफार्म वर्कर बन गए हैं उनको किसी भी तरह के पेंशन, पीएफ और ऐसी स्थायी लाभ की योजनाओं से दूर रखा गया है। इन संहिताओं को लागू करने में सरकार हिचक रही थी क्योंकि खेती से जुड़े तीनों कानूनों का भारी विरोध हुआ और अंततरू उन्हें वापस लेना पड़ा। तब इनको लेकर भी नाराजगी दिख रही थी और मजदूर संगठन विरोध की तैयारी में थे। इन छह वर्षों में वह सब स्थिति बदल गई है। विद्यार्थी परिषद के नंबर एक होने के बाद शिक्षा के निजीकरण समेत किसी भी मुद्दे पर छात्रों के आंदोलित होने का खतरा नहीं रहा तो बीएमएस के नंबर एक मजदूर संगठन बनाने से मजदूरों का आंदोलन भी दूर की चीज हो गई है। और इस बीच सरकार ने संहिताओं की अधिसूचना रोक कर राज्यों से कहा कि वे अपने हिसाब से कानून बना लें। टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि अब तक 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कंपनी के लिए न्यूनतम 300 मजदूर वाली सीमा बढ़ा दी है। 25 राज्यों ने ठेका मजदूरी वाले प्रावधानों को लागू कर दिया है और 31 राज्यों ने महिला मजदूरों से नाइट शिफ्ट कराने का कानून भी ला दिया है। यह साफी यही कि पुराने 29 कानूनों से कई तरह की दिक्कत थी–नियोक्ताओं से ज्यादा मजदूरों को थी कि प्रावधान परस्पर विरोधी थे। लेकिन इस बार के बदलाव ने तो तराजू का पलड़ा मालिकों की तरफ मोड़ दिया है और कमाल यह है कि कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है।

बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाया गया दवा बाजार

आर. सूर्यमूर्ति

हर देश आखिरकार यह तय करता है कि हेल्थकेयर एक अधिकार है या कमाई का जरिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दोनों हो सकता है। कमेटी ने आखिरकार इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया है। अब यह सरकार पर है कि वह टूटी हुई मूल्य निर्धारण व्यवस्था में सुधार करेगी– या उस इंडस्ट्री को बचाती रहेगी जिसने नियामक कमजोरी को आर्थिक हक समझ लिया है। किसी भी मायने में, भारत बीमार लोगों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती जगह होनी चाहिए। यह जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। फिर भी आम भारतीयों के लिए, असल अनुभव इसके उलट हैरू एक हेल्थकेयर सिस्टम जहां एक साधारण बुखार की दवा की कीमत उसकी आपूर्ति की कीमत से छह गुना, गैस्ट्रिक की गोली की कीमत दस गुना, और एक जान बचाने वाली कैंसर की दवा की कीमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी छपी हुई श्अधिकतम खुदरा कीमतश से लगभग 80 प्रतिशत कम हो सकती है। यह साफ है कि इस बाजार को इलाज तक जनता की पहुंच और उनकी खर्च वहन करने की क्षमता के अनुरूप नहीं, बल्कि उनका दोहन कर भारी लाभ अर्जित करने के अनुरूप बनाया गया है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी की ताजा रिपोर्ट अपने डायग्नोसिस में बहुत सख्त है, परन्तु अभी भी उसमें पर्याप्त कठोरता नहीं है। कमिटी ने उस बात को बहुत ध्यान से दस्तावेज के रूप में रिकार्ड किया है जो मरीज दशकों से जानते हैंरू कि भारत की दवाओं की मूल्य निर्धारण प्रणाली दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक खुला मैदान है, खासकर उन बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए जिनके ब्रांडेड जेनेरिक उस श्रेणी की दवाओं पर हावी हैं जिन पर लोग हर दिन भरोसा करते हैं। कमिटी लिखी गयी कीमतों को श्अतार्किक,श श्बहुत ज्यादा,श और श्जनहित के खिलाफश कहती है। यह तो ठीक है। असलियत इससे भी बुरी हैरू पूरी प्रणाली निर्धारित मूल्य मुद्रास्फीति, नियामक की अनुपस्थिति, और एक राजनीतिक प्रतिष्ठान पर बना है जो एक ऐसे उद्योग का सामना करने को तैयार नहीं है जो बिना किसी सजा के बहुत ज्यादा सहजता से काम कर रही है। रिपोर्ट में दिए गए नंबर चौंकाने वाले हैं। 21 रुपये की एमआरपी वाली एक आम एंटीहिस्टामाइन टैबलेट एक स्टॉकिस्ट को मात्र 1 रुपये 85 पैसे में दी जाती हैकृ जो 1,038 प्रतिशत है। एक स्टैंडर्ड एसिड–रिफ्लक्स दवा जिसकी कीमत 170 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र 13.95 रुपये की पड़ती है, जो 1,119 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। एक आम तौर पर लिखी जाने वाली कैल्शियम सप्लीमेंट की कीमत में तो हद हो गयी हैरू 16.95 रुपये की आपूर्ति कीमत के मुकाबले एमआरपी 327 रुपये है, यानी 1,831 प्रतिशत का मार्जिन। ये कभी–कभार होने वाली गड़बड़ियां नहीं हैंय ये बिजनेस मॉडल है। कमेटी ने एलर्जी, गैस्ट्रो, विटामिन, कार्डियोवैस्कुलर और बच्चों की दवाओं में भी ऐसी ही गड़बड़ियां पाईं– दूसरे शब्दों में, ये भारत की दवाइयों की टोकरी का दिल हैं। सबसे ज्यादा ज्यादतियां ऑन्कोलॉजी में दिखती हैं– जहां दांव सचमुच जिंदगी और मौत का होता है। कैंसर की एक दवा, जिसका एमआरपी 38,215 रुपये है, ऑनलाइन 9,200 रुपये में बिकती है। दूसरी, जिसकी आनलाइन उपलब्धता लिस्ट पर मूल्य 45,000 रुपये है, रिटेल में 8,800 रुपये में मिलती है। दुनिया का कोई भी भरोसेमंद मूल्य निर्धारण इकोसिस्टम इतना ज्यादा अंतर नहीं दिखाता, जब तक कि मूल कीमत को बनावटी तौर पर न बढ़ाया जाए। कमेटी, जो आमतौर पर अपनी भाषा को लेकर सावधान रहती है, यहां ईमानदारी से कहती हैरू श्ये एमआरपी ज्यादा ट्रेड मार्जिन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।श जब कोई मरीज परेशान होता है, जब परिवार किसी को जिंदा रखने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहे होते हैं या अपनी बचत खर्च कर रहे होते हैं, तो कंपनियों को पता होता है कि वे बिना किसी नतीजे के कीमतें बढ़ा सकती हैं। फिर सरकार, जो इस पैटर्न को पूरी तरह जानती है, नजरअंदाज कर देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दखल देने के लिए कानूनी ढांचा नहीं है। उसके पास एनपीपीए है, जो एक मूल्य नियंत्रक हैय ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर है, जो एक कानूनी ढांचा हैय और सस्ती दवाओं के लिए एक घोषित राष्ट्रीय वायदा है। लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है। एनपीपीए एक बिना दांत वाला वॉचडॉग है। यह दवा उत्पादन लागत का ऑडिट नहीं कर सकता। यह कॉस्ट शीट की मांग नहीं कर सकता। यह ट्रेड मार्जिन के खुलासे को जरूरी नहीं कर सकता। यह किसी भी नॉन–शेड्यूल्ड दवा की

लॉन्च प्राइस को नियंत्रित नहीं कर सकताकृ जो एक ऐसी श्रेणी है जो आसानी से भारत के दवा बाजार के 85 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में छाया रहता है। इस बीच, सरकार जन औषधि को जनता की क्रय शक्ति की पहुंच में रखने की अपनी प्रतिबद्धता के सुबूत के तौर पर पेश करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जन औषधि नीति की जीत नहीं बल्कि उसका दोष है। जब वही मॉलिक्यूल सरकारी दुकान पर 12 रुपये में बिकता है जिसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी 170 रुपये में बेचती है, या जब कोई सप्लीमेंट जो सरकारी फार्मेसी में 40 रुपये में बिकता है, उसकी कीमत ब्रांडेड लेबल के तहत 327 रुपये हो, तो नतीजा साफ हैरू बहुत ज्यादा एमआरपीन तो स्वाभाविक हैं और न ही जरूरी। लेकिन उनकी इजाजत है। अस्पताल इन नियंत्रित कीमतों के ऊपर जीएसटी, प्रोसिजरल फीस और श्पैकेज चार्जश लगा रहे हैं, और चुपचाप उसी बोझ को फिर से बढ़ा रहे हैं जिसे खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। जब दखल प्रतीकात्मक हो जाता है, तो मुनाफाखोरी ढांचागत हो जाती है। असली दुखद बात यह है कि सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन पर पूरी तरह से फेल है। जब टीएमआर को कुछ समय के लिए 42 कैंसर दवाओं पर लागू किया गया, तो एमआरपी50 प्रतिशत तक गिर गए। मरीजों ने एक साल में लगभग 984 करोड़ रुपये बचाए। जब महामारी के दौरान कुछ मेडिकल डिवाइस पर टीएमआर लागू किया गया, तो इससे और 1,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। फिर भी टीएमआर पांच साल से रुका हुआ है, मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स और उनके घरेलू सहयोगियों के भारी असर वाले कंसल्टेशन में फंसा हुआ है। कमेटी इस सच्चाई का सीधे तौर पर नाम नहीं लेती है, लेकिन इंसेंटिव्स को समझने के लिए किसी फोरेंसिक ऑडिटर की जरूरत नहीं है। भारत एक ग्लोबल फार्मा पावरहाउस बनने के लिए पागल है, लेकिन अगर वह अपने देश में प्राइसिंग पावर के गलत इस्तेमाल का सामना करने से इनकार करता है, तो वह एक ही समय में दुनिया का आपूर्तिकर्ता और अपनी आबादी का रक्षक नहीं हो सकता। यह उलटापन बहुत अजीब हैरू भारत 200 से ज्यादा देशों को कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है, लेकिन उसके अपने नागरिक अक्सर उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए कहीं ज्यादा पैसे देते हैं। देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ–ईस्ट एशिया में सस्ती दवाइयां निर्यात एक्सपोर्ट करता है, जबकि घरेलू डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को ऐसे मार्जिन कमाने की इजाजत देता है जिन्हें उन्हीं देशों में अनैतिक माना जाएगा – अगर गैर–कानूनी नहीं तो। भारत के पास दवा की कीमतों पर डेटा की कमी नहीं है– उसके पास फैसले लेने की कमी है। यह शर्म की बात है कि कैंसर की दवाओं की कीमतें लग्जरी चीजों की तरह हैं। यह भी शर्म की बात है कि बहुत ज्यादा एमआरपीइसलिए बनी हुई हैं क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले मरीज का पक्ष लेने से इनकार करते हैं। हर देश आखिरकार यह तय करता है कि हेल्थकेयर एक अधिकार है या कमाई का जरिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दोनों हो सकता है। कमेटी ने आखिरकार इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया है। अब यह सरकार पर है कि वह टूटी हुई मूल्य निर्धारण व्यवस्था में सुधार करेगी– या उस इंडस्ट्री को बचाती रहेगी जिसने नियामक कमजोरी को आर्थिक हक समझ लिया है। अगर भारत सच में दुनिया की फार्मेसी बनना चाहता है, तो उसे पहले अपने ही लोगों को दिवालिया बनाना बंद करना होगा।

प्रत्येक महिला को सशक्त बनाना, प्रत्येक समुदाय का उत्थान करना-अमृत काल में नारी शक्तिका नया दौर

अन्नपूर्णा

जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो राष्ट्र का उत्थान होता है समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज में, महिला की गरिमा से कतई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारे समग्र कार्यक्रम– मिशन शक्ति– के जरिए इसे संस्थागत ढांचे में बदलकर इस विश्वास को फिर से मजबूत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा है, हमारी सरकार महिलाओं के लिए ‘सम्मान’ और ‘सुविधा’ को सबसे ज्यादा महत्व देती है।‘ये मार्गदर्शक शब्द केवल भावनाएँ मात्र नहीं, अपितु वह नींव हैं, जिस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत भारत के कोने–कोने में मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं। इस प्रयास के केंद्र में मिशन शक्ति की संबल‘ उप–योजना के तहत चलने वाले वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं। 2015 में शुरू हुए ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एकीकृत सहायता तंत्र प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें खामोश रहकर पीड़ा न सहनी पड़े और न ही बिखरी हुई सहायता प्रणालियों के बीच भटकना पड़े। आज तक, पूरे भारत में 862 ओएससी चल रहे हैं, जिनसे 12.20 लाख से ज्यादा महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत मदद मिली है। डर से आजादी तक, खामोशी से सहायता तक – ओएससी ऐसे स्थान हैं जहाँ से घाव भरने की शुरूआत होती है। ये केंद्र प्रतिक्रियात्मक शासन से आगे बढ़कर सक्रिय शासन का रुख करते हैं। चाहे किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का सामना करना पड़े, ओएससी उसके पुनर्वास, गरिमा और न्याय दिलाने में मदद करने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र अस्पतालों के भीतर या उनके पास स्थापित किए गए हैं, ताकि तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके – जो मुश्किल समय में पहला जरूरी कदम है। महिला हेल्पलाइन (181) का सार्वभौमीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संकट से घिरी महिलाओं के लिए 24–7 मदद सुनिश्चित करके ओएससी का पूरक बनता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित यह हेल्पलाइन अब तक 2.56 करोड़ से अधिक कॉल संभाल चुकी है और 93.48 लाख से अधिक महिलाओं की मदद कर चुकी है (30 सितंबर तक)। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112) से एकीकृत यह हेल्पलाइन संकट और राहत के बीच की दूरी को पाटती है। व्यवस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और तेजी से न्याय पहुंचाने के लिए, हमने 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनमें से 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय हैं। इन न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है, अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। सुनाया गया प्रत्येक फैसला, बहाल किया गया प्रत्येक अधिकार न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। न्याय मिलना अब प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाधित नहीं होता, और प्रत्येक सर्वाइवर समय पर राहत की उम्मीद कर सकता है। इसके साथ ही, हम पुलिस स्टेशनों पर 14,658 महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) के साथ जमीनी स्तर को मजबूत कर रहे हैं, जिनमें से 13,700 से ज्यादा की कमान महिलाएँ संभाल रही हैं। ये डेस्क सर्वाइवर्स में अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता मिलती है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मजबूत करती है। हम 807 एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) के जरिए मानव तस्करी से भी निपट रहे हैं और निर्भया कोष के तहत रेलवे और सड़क परिवहन सेवाओं में आपातकालीन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के जरिए सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम कि महिलाओं का सुरक्षित रूप से यात्रा करना, निडर होकर काम करना और सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना सुनिश्चित करते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण सिर्फ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास और सशक्तिकरण तक व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी पहलों के जरिए, हम सोच बदल रहे हैं और सम्मान, बराबरी और अवसर के मूल्य स्थापित कर रहे हैं। पीएमएमवीवाई और सखी निवास के जरिए, हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो महिलाओं को सिर्फ सर्वाइवर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति में हितधारकों के तौर पर भी महत्व देती हैं। हमारे सखी निवास हॉस्टल, जिनमें से कई शहरी प्रत्येक और अर्ध–शहरी इलाकों में हैं,– 26,000 से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह दे रहे हैं जिससे वे बिना किसी डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं। मिशन शक्ति के तहत हमारी रणनीति एकीकरण, समन्वय और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। संकल्परू हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की शुरुआत के साथ, हमने स्थानीय क्रियान्वयन में एक रणनीतिक परत जोड़ी है, जिससे महिलाएँ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण और समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इन केंद्रों के जरिए 27 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सरोकार है। प्रत्येक निर्मित ओएससी, प्रत्येक हेल्पलाइन कॉल जिसका उत्तर दिया गया, ।

यूपी की लगातार दूसरी जीत

लखनऊ, (संवाददाता)। सुभाष बोया के बहुमुखी प्रदर्शन (नाबाद 36 रन और चार विकेट) की बदौलत मेजबान उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने एकतरफा मुकाबले में राजस्थान को दस विकेट से करारी मात दी। अन्य मुकाबलों के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब ने जीत दर्ज की। पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम खराब शुरुआत के चलते उबर न सकी। देखते ही देखते पूरी का पुलिंदा 15.2 ओवर में 66 रन पर बंध गया। जसराज सिंह (22) सर्वोच्च स्कोर रहे। सुभाष बोया ने दस रन देकर चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जवाब में उत्तर प्रदेश ने महज 3.4 ओवर में बिना विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सुभाष बोया ने गेंदबाजी

के बाद बल्लेबाजी में हाथ दिखाते हुए 36 रन बनाए, जबकि चंदन 17 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रतियोगिता के दूसरे मुकाबले में महाराष्ट्र ने हरियाणा को नौ विकेट से करारी मात दी। हरियाणा के 130 रन के लक्ष्य को महाराष्ट्र ने 13.1 ओवर में एक विकेट खोकर प्राप्त किया। विजेता टीम से सीताराम ने 66 और आशीष ने 31 रन बनाए, जबकि महेश ने दो विकेट लिए। तीसरे लीग मुकाबले में मध्य प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को चार विकेट से हरायाा। हिमाचल प्रदेश के 193 रन के लक्ष्य को मध्य प्रदेश ने 17.5 ओवर में चार विकेट खोकर प्राप्त किया। विजेता टीम से मो. शहजाद ने 75 और रजत ने 70 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि पराजित टीम से रत्नेश ने 58 और अजय ने 53 रन बनाए। प्रतियोगिता के चौथे मुकाबले में पंजाब ने बिहार को 38 रन से पराजित किया। पंजाब के 225 रन के जवाब में बिहार की टीम 20 ओवर में दो विकेट खोकर 187 रन बना सकी। विजेता टीम की ओर से जतिंदर कुमार ने 74 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 137 रन की शतकीय पारी खेली।

स्कूल गेम्स में जोर-आजमाइश जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ स्कूल गेम्स के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो–खो और कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। बैडमिंटन टीम इवेंट के अंडर–14 व अंडर–17 बालिका वर्ग में क्रमशरू मॉडर्न अकादमी व गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की टीमें विजेता बनीं। वहीं अंडर–17 बालक वर्ग में सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट स्कूल ने खिताब जीता। दूसरी ओर एकल बैडमिंटन में सक्षम वर्मा, प्रगेश व परिनीत सहित ऋदिमा अपने वर्गों में चौंपियन बने। अंडर–14 बालक एकल में में सक्षम वर्मा (द मिलेनियम स्कूल) ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर–17 बालक में पी सिंह पहले, अनुज कुशवाहा दूसरे व शिवांश तीसरे स्थान पर रहे। अंडर–19 बालक में परिनीत पहले, निखिल दूसरे व पराग

शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। दूसरी ओर अंडर–17 बालिका में ऋद्धिमा पहले, अंशिका दूसरे व आकांक्षा तीसरे स्थान पर रहे। वॉलीबाल बालक अंडर–14 और 17 बालक में लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर डी, कानपुर रोड विजेता रही, जबकि बालक अंडर–19 का खिताब लखनऊ पब्लिक स्कूल, साउथ सिटी ने जीता। अंडर–14 व अंडर–17 बालिका में गांधी कॉलेज चौंपियन बनी जबकि बालिका अंडर–19 में सेंट जोसेफ स्कूल, राजाजीपुरम ने बाजी मारी। बालिका अंडर–17 व अंडर–19 कबड्डी में लखनऊ पब्लिक कॉलेज, ए ब्लॉक, राजाजीपुरम ने श्रेष्ठता साबित की।

संक्षिप्त खबरें

नगर निगम का संपूर्ण समाधान दिवस

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम और जलकल विभाग से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और उनके निस्तारण के लिए लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इसमें महापौर सुषमा खर्कवाल समस्याओं को सुनेंगी। यहां शहरवासी सफाई, मार्ग प्रकाश, पार्क, सड़क निर्माण व गृहकर–जलकर आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यदि किसी भवन स्वामी की गृहकर से जुड़ी शिकायत हो तो वह अपने मकान की सामने से फोटो, आवेदन पत्र और पुराना बिल जरूर लाए, जिससे यह पता चल सके मकान का उपयोग आवासीय है या व्यावसायिक। फोटो में यह दिखना चाहिए कि मकान कितने मंजिल बना है। इससे शिकायत का निस्तारण आसानी से होगी।

ट्रॉमा में लगेगी नई एआई स्कैनर सीटी स्कैन मशीन

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में नई एआई स्कैनर सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। मशीन लगाने के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन होगा। एक माह में निर्माण पूरा कर मशीन लगा दी जाएगी। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सड़क हादसों में घायल होने वालों के लिए शुरुआती एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। पुरानी मशीनों में मरीज का नाम–पता टाइप करने और उन्हें लिटाकर सेट करने में समय बर्बाद होता था, जो अब नहीं होगा। रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि नई मशीन में इमरजेंसी मोड है। मरीज के स्ट्रेचर पर आते ही बिना डाटा एंट्री के स्कैन शुरू हो जाएगा। इसका स्मार्ट कैमरा मरीज को अपने आप सही स्थिति में सेट कर देता है। डॉ. केके सिंह ने बताया कि हादसों के बाद कई बार रीढ़ की हड्डी या पसलियों के फ्रैक्चर पकड़ में नहीं आते हैं। इस मशीन का एआई सिस्टम रीढ़ और पसलियों की 3डी तस्वीर बनाकर खुद बता देगा कि चोट कहां लगी है। इसका खास कैमरा दिमाग की महीन नस की चोट को भी साफ दिखाएगा। दर्द के कारण मशीन पर लेटे मरीज अकसर हिलते–डुलते हैं, जिससे फोटो धुंधली आती है। नई मशीन मरीज के हिलने को खुद ठीक कर साफ फोटो देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुरानी मशीनों के मुकाबले 80 फीसदी कम रेडिएशन निकलता है।

नगर निगम ने विरोध के बीच 200 कब्जे हटाए

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम ने बृहस्पतिवार को कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान विरोध के बीच सड़कों व पटरियों से करीब 200 कब्जे हटाए गए। जोन एक के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह की अगुवाई में श्रीराम टावर वाली रोड और मीराबाई मार्ग पर अभियान चलाया गया। टीम ने सड़क के दोनों ओर से ठेले–गुमटी वालों का हटाया। यहां अतिक्रमण के चलते लोगों का आने–जाने में परेशानी हो रही थी। इंदिरानगर में कंचना बिहारी मार्ग से टेढ़ी पुलिया और उसके आसपास व सेक्टर–14 तक कार्रवाई की गई। वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर–आठ में सड़क, पटरी से कब्जेदारों को हटाया गया।

मानसिक रूप से कमजोर युवती का शव तालाब में मिला

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी के बेहटा गांव में बृहस्पतिवार सुबह तालाब में रेनू रावत (26) का शव पड़ा मिला। वह बुधवार शाम से लापता थी। परिजनों ने तालाब में शव उतराता देखकर उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। रेनू के पिता लक्ष्मण रावत ने बताया कि उनकी बेटी अविवाहित थी और मानसिक रूप से कमजोर थी। रेनू को अक्सर मिर्गी के दौरे भी आते थे। रेनू के परिवार में पांच बहनें और दो भाई हैं। काकोरी थाने के अतिरिक्त निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। कोई तहरीर भी नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आईसीयू में जूता पहनकर घूम रहे कर्मचारी, तीमारदार

लखनऊ, (संवाददाता)। लोहिया संस्थान की वेंटिलेटर यूनिट में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। कर्मचारी और तीमारदार जूते पहनकर यूनिट में घूम रहे हैं। इन्हें यूनिट में प्रवेश करने से पहले शू–कवर मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। इससे गंभीर मरीजों में संक्रमण

का खतरा बढ़ गया है। संस्थान में इमरजेंसी वार्ड के पास आईसीयू–एचडीयू है। कर्मचारी और तीमारदार इसमें बिना कवर किए जूते पहनकर मरीजों के बेड तक पहुंच रहे हैं। यहां तीमारदारों को मास्क लगाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। कर्मचारी एक ही वक्त में कई मरीजों को हाथ लगा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर इलाज की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। आईसीयू–एचडीयू यूनिट में लोग बिना रोकटोक आ–जा रहे हैं। इससे गंभीर मरीजों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। संस्थान के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद्र तिवारी के मुताबिक, आईसीयू–एचडीयू के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। कर्मचारी व तीमारदार जूते पहनकर घूम रहे हैं तो इसे रोका जाएगा।

क्वीन मेरी में सुस्त सर्वर ने किया परेशान

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग (क्वीन मेरी) में बृहस्पतिवार को सुबह से दोपहर तक सर्वर की सुस्त रफ्तार रही। इस कारण परचा बनाने से लेकर कैश काउंटर तक पर लंबी कतारें लगी रहीं। काफी मरीजों का समय रसीद बनवाने में निकल गया, लेकिन वे जांच नहीं करवा पाए। कुछ मरीजों की तो रसीद ही नहीं बन सकी। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। सर्वर की धीमी रफ्तार के कारण जांच के लिए रसीद बनवाने के लिए सुबह दस बजे से कतार में लगीं महिलाओं का दोपहर एक बजे तक नंबर नहीं आया। जिनकी बारी आई, वे भी सर्वर सही होने का घंटों इंतजार करती रहीं। इस दौरान कई महिलाएं थककर जमीन पर ही बैठ गईं। दोपहर एक बजे काउंटर के सामने लंबी कतार देखने को मिली। इंदिरानगर से बहन का इलाज कराने पहुंचीं रेशमा ने बताया कि रसीद न बन पाने से जांच नहीं हो सकी। अब शुक्रवार को फिर आना पड़ेगा। इस बीच उनकी बहन की हालत और खराब हो रही है। उधर, काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर की जगह अब नेक्सॉन सॉफ्टवेयर लाया गया है। इसके

बाद से परेशानी आ रही है। जो काम पहले पांच मिनट में होता था, अब उसमें दस मिनट लग रहे हैं। सर्वर की सुस्ती भी दिक्कत बढ़ा रही है। खुर्रमनगर निवासी पल्टू ने बताया कि उनकी बेटी सीतापुर से इलाज करवाने आई थी। सुबह से कतार में लगने के बावजूद दोपहर डेढ़ बजे तक नंबर नहीं आया। रसीद लेने में ही पूरा समय निकल गया। जांच के लिए शुक्रवार को फिर आना होगा। उधर, केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर की वजह से समस्या आई होगी। पहले इस्तेमाल हो रहा सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो गया था। विभाग ने सर्वर के सुस्त होने की जानकारी नहीं दी। इसकी जानकारी मिलती तो समस्या का तुरंत हल निकाला जाता। इस संबंध में जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

उत्तर प्रदेश में मनरेगा में मानव दिवस सृजन में देश में प्रथम स्थान

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में राज्य के ग्राम्य विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में नए आयाम स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में रोजगार सृजन के वार्षिक भौतिक लक्ष्य 2000 लाख मानव दिवस निर्धारित किए गए थे, जिनमें अब तक 1768.81 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ प्रदेश मानव दिवस सृजन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक मनरेगा के तहत 47.76 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है और इस पर कुल 6,598.89 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा अभिसरण (कन्वर्जेंस) के तहत कराए जाने वाले कार्यों में अन्य लाइन विभागों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और फील्ड स्तर पर ठोस कदम उठाकर योजनाओं की प्रगति और मानव दिवस सृजन को बढ़ाया जाए।उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मनरेगा के तहत जिन श्रमिकों ने 90 दिन तक कार्य किया है, उन्हें बीओसीडब्ल्यू बोर्ड (श्रम विभाग) में पंजीकृत कराकर श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।राज्य स्तर पर बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त, ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी ने भी मानव दिवस सृजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पलायन को रोकना है और यह तभी संभव है जब श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी जनपद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानव दिवस सृजन में किसी भी प्रकार की गिरावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेरणा और निरंतर निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश की मनरेगा योजना ने ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड की स्थापना की है।

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा–2025 के लिए समाज कल्याण विभाग की नि:शुल्क कोचिंग योजना

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। यूपीपीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा–2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में किया जाएगा।संस्थान के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो यूपीपीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा–2025 में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा।आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी।

बीबीएयू में 'नवाचार डिजाइन और उद्यमिता' पर द्विदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

लखनऊ, (संवाददाता)। स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 4 दिसंबर को 'नवाचार डिजाइन और उद्यमिता' विषय पर आधारित द्विदिवसीय क्षमता

निर्माण कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। यह राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 55 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रतिनिधियों और सदस्यों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और डिजाइन थिंकिंग को बढ़ावा देना है। यह आयोजन बीबीएयू, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पीएम श्री स्कूल, स्कूल इनोवेशन काउंसिल और वाधवानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हो रहा है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एडीशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर विष्णु कांत पांडेय मौजूद रहे। मंच पर रिजनल ऑफिसर, इनोवेशन सेल, शिक्षा मंत्रालय शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, इनोवेशन एवं डिजाइन थिंकिंग विशेषज्ञ अम्बुमति, नोडल सेंटर हेड प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा और को–ऑर्डिनेटर डॉ. अर्पित शैलेश भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय के कुलगीत के पश्चात अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया। सत्र का औपचारिक संचालन डॉ. नरेंद्र सिंह ने किया।सर्वप्रथम नोडल सेंटर हेड प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में नई सोच, नए प्रयोगों और व्यावहारिक नवाचारों को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट मंच है, जहां देशभर के शिक्षा अधिकारी एक साथ जुटकर अनुभव साझा करेंगे और नई रणनीतियों पर विचार करेंगे।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में नवाचार, डिजाइन और उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला है। भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, और यदि यह युवा शक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग सही दिशा में करे तो विकास की असीम संभावनाएँ साकार हो सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को पुनः वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने होंगे। यह लक्ष्य तभी संभव है जब युवा नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता अपनाएँ। उन्होंने युवाओं से असफलता के भय से मुक्त होकर नवाचार और उद्यमिता के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।मुख्य अतिथि विष्णु कांत पांडेय ने पीएम श्री स्कूल योजना की महत्ता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना विद्यालयी शिक्षा को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालय स्तर पर ही नवाचार और उद्यमिता के बीज बोना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं, जहां बच्चों को तकनीकी प्रयोगों, नवाचार और समस्या–समाधान पर कार्य करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा अपने नए विचारों को वास्तविक रूप देता है, तो न केवल उसका स्वयं का व्यक्तित्व विकसित होता है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा भी मजबूत होती है।कार्यशाला के दौरान नवाचार एवं उद्यमिता की विद्यालयों में भूमिका, मानव–केंद्रित डिजाइन थिंकिंग, समस्या–समाधान है।

नारकोटिक दवाओं के अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश ने नारकोटिक दवाओं के अवैध व्यापार, उनके डायवर्सन और नशे के रूप में दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक माह का विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाया। इस व्यापक अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 40 जनपदों में कोडिन युक्त सिरप सहित अन्य नियंत्रित दवाओं की खरीद, भंडारण और बिक्री की तकनीकी और सघन जांच की गई। जांच में अनियमितताएं मिलने पर विभाग द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई।अभियान के दौरान विभाग ने नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रांची समेत अन्य राज्यों की फर्मों से प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से एकत्र कर उनका विश्लेषण किया। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर जिलों में छापेमारी, निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे अवैधा गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस संपूर्ण अभियान में मुख्यालय से नियुक्त दो ड्रग इंस्पेक्टरकृवैभव बब्बर और सीमा सिंहकृकी विशेष सराहना की। दोनों निरीक्षकों ने जमीनी स्तर पर जांच, सूचना विश्लेषण, आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रशासनिक समन्वय में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभागीय मंशानुरूप कार्य करने वाले इन दोनों निरीक्षकों तथा मुख्यालय के अन्य संबंधित ड्रग इंस्पेक्टरों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी प्रकार की कठोर और सतत कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अवैध नारकोटिक दवाओं के कारोबार पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को नया आयाम, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को मिलेगा लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और इको–टूरिज्म की तस्वीर तेजी से बदल रही है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों के सुरक्षित आवास, प्राकृतिक परिदृश्य का संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के विस्तार ने राज्य को प्रकृति प्रेमियों का नया पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वन, सिंचाई सहित अन्य विभागों के समन्वय से पर्यटकों के लिए आकर्षक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उनका कहना है कि वन्य जीव संरक्षण को सुदृढ़ करते हुए स्थानीय समुदाय को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गैंडा, बाघ, बारहसिंघा, घड़ियाल जैसी दुर्लभ प्रजातियां न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि उनके लिए आवासीय और पर्यावरणीय वातावरण भी विकसित किया गया है। दुधवा, पीलीभीत, कतर्नियाघाट, अमानगढ़ और सोहगीबरवा जैसे वन क्षेत्र पर्यटकों को विशेष अनुभव प्रदान करते हैं। तराई, ब्रजभूमि, गंगा नदी का क्षेत्र, बुंदेलखंड और विंध्य वनक्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।इको–टूरिज्म विकास बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों में 161 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर विभिन्न प्राकृतिक स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया है। इन सुविधाओं में मार्ग सुधार, कैफेटेरिया, इको–फ्रेंडली विश्राम स्थल, गजिबो, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग स्थान और बच्चों के खेलने के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं को पर्यावरण–संवेदनशील तरीके से विकसित किया गया ताकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।वन विभाग के सतत प्रयासों से वन्य जीवों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 की वन्य पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार दुधवा नेशनल पार्क में 65 हजार से अधिक, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 12 हजार और बफर जोन में 14 हजार से अधिक वन्य प्राणी पाए गए। वर्ष 2025 के नवीनतम सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संख्या बढ़कर 1.13 लाख से अधिक, कतर्नियाघाट में 17 हजार से अधिक और बफर जोन में लगभग 15 हजार तक पहुंच गई। इसी अवधि में गुलदार तेंदुए की संख्या 92 से बढ़कर 275 और गैंडों की संख्या 49 से 66 हो गई। यह आंकड़े प्रदेश में संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इको–टूरिज्म को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए दुधवा, पीलीभीत और कतर्नियाघाट में नेचर गाइड्स को प्रशिक्षण दिया गया है। थारू जनजाति को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर उनके पारंपरिक खानपान और संस्कृति को सैलानियों तक पहुँचाने की पहल की जा रही है। स्थानीय निवासियों को होम–स्टे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़े और पर्यटकों को स्थानीय जीवनशैली का वास्तविक अनुभव मिले।उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि वन्य जीव संरक्षण और इको–टूरिज्म एक–दूसरे के पूरक बनकर राज्य के समग्र विकास में योगदान दें। प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश का प्रमुख इको–टूरिज्म हब बनने की दिशा में अग्रसर है।

सर्दी की दस्तक के चलते तैयारियों से उतरा स्वास्थ्य विभाग मरीजों को ठंड से बचाने के लिए सीएचसी पीएचसी पर किए बचाव के इंतजाम

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। अब मौसम बदल रहा है।जैसे–जैसे दिसंबर की ठिठुरन बढ़ रही है।वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग सर्दी जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कोल्ड वेव और शीतलहर को देखते हुए जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हर स्तर पर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रही इस विशेष तैयारी का अयोध्या में साफ असर दिख रहा है।इस संबंध मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बनियान ने बताया कि जिले की सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयल इमरशन हीटर लगवा दिए गए हैं। इसके अलावा नवजात शिशु वार्ड, प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर में भी विशेष हीटर की व्यवस्था की गई है, ताकि नवजात बच्चों और मरीजों को ठंड से बचाया जा सके। बच्चों और बुजुर्गों पर सर्दी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए इन वार्डों को पूरी तरह गर्म रखने के लिए अलग से हीटर रखवाए गए हैं। दवाओं की कोई कमी न रहे, इसके लिए भी खास ध्यान दिया गया है। सर्दी–जुकाम, निमोनिया, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों की सभी जरूरी दवाइयां जिला अस्पताल, सीएचसी के साथ–साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दी गई हैं। मरीजों को मोटे गर्म कंबल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अस्पतालों की पुरानी इमारतों में जहां खिड़कियां टूटी हुई थीं या खुली रहती थीं, उन्हें बंद कराने और मरम्मत कराने का काम तेजी से चल रहा है।

डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट डॉ अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी आशा बहनें घर–घर जाकर लोगों को शीतलहर से बचाव के उपाय बताएंगी। गर्म कपड़े पहनना, बच्चों को ठंड से बचाना, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, रात में अलाव जलाना जैसे संदेश घर–घर पहुंचाए जा रहे हैं। शासन से आए बैनर–पोस्टर सभी स्वास्थ्य केंद्रों और गांवों में लगाए जा रहे हैं।सीएमओ कार्यालय में एक बार फिर से कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। शीतलहर को लेकर रोजाना दोपहर दो बजे शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है। कोल्ड रूम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अजित सिंह व एसपी यादव को लगाया गया है। बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सतर्क है ताकि सर्दी के मौसम में किसी भी मरीज को परेशानी न हो।ठंड अभी और बढ़नी बाकी है,लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां देखकर लगता है कि इस बार अयोध्या की जनता को सर्दी से डरने की जरूरत नहीं है।

बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर राजेन्द्र गौतम ने माल्यार्पण किया

हरदोई। साड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर बघौली स्थिति पर अपना दल एस हरदोई जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गौतम ने बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारत के नागरिक बाबासाहेब या भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं , ने 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही अंतिम सांस ली। समाज में डॉ. अंबेडकर के बहुमूल्य योगदान की स्मृति में, इस दिन को पूरे भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब ,बुद्ध और उनका धम्मश नामक पुस्तक पर काम कर रहे थे। पुस्तक पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। नागपुर में वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद, 14 अक्टूबर 1956 को बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक विपिन कुमार, सुभाष देवेंद्र कुमार बाबा दुबेचंद, आदि सैकड़ों लोगों मौजूद रहे हैं

संक्षिप्त खबरें

अनुपस्थित रहे आधा दर्जन से अधिक रोडवेज चालकों पर हुई कार्यवाही – आदित्य प्रकाश

अयोध्या। शनिवार को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे सात रोडवेज चालकों का एक दिन का वेतन स्थगन किमी के बराबर सहायक प्रबंधक रोडवेज आदित्य प्रकाश ने कार्यवाही करते हुए काटा है।उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही लगातार रोडवेज चालकों द्वारा किए जा रहे लापरवाही के चलते किया गया।बताया कि जिन चालकों का वेतन विभाग द्वारा काटा गया है।उन चालकों मे विमल कुमार,लक्ष्मी नारायण मिश्रा, शैलेंद्र प्रताप सिंह, उमाशंकर, मनोज कुमार सिंह,सी पी सिंह व नरेंद्र कुमार शामिल है।बताया कि यह कार्यवाही भविष्य में अनुपस्थित रहने वाले रोडवेज चालकों पर की जायेगी।सभी चालकों व परिचालको को निर्देश दिया है कि बिना कार्यालय को सूचित किया मुख्यालय से बाहर नहीं रहे नहीं तो उनके खिलाफ भविष्य मे विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

जब मतदाता पुनरीक्षण सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो सपा की विदाई सुनिश्चित है : केशव प्रसाद मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,06 दिसंबर । यूपी के जौनपुर में खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता ने निधन पर शनिवार को उनके पैतृक आवास समसपुर गांव पहुंच कर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया।इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें संबल प्रदान किया।पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मीडिया से बात करते हुए अप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा दिया है के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बाबा साहेब पर संविधान पर बोलेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।जब वो सत्ता में थे तो बाबा साहब को और संविधान को कुचलने और अपमानित करने का काम किया है यहां तक कि उनके अनुयाईओ को भी बहुत कष्ट देने का काम किया है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने सवाल उठाया कि मक्का मदीना में सीसीटीवी कैमरे लगे तो मदरसों और मस्जिदों में क्यों नहीं इस पर कहा कि उनका सवाल जायज है निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए जल्द ही भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी यूपी के सभी सभी मदरसों पर लगेगे।ै प्‍ पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का एक पवित्र महायज्ञ है। जो बूथ लूट का चुनाव जीतने का काम करते थे अब उनका युग खत्म हो गया है। जब मतदाता पुनरीक्षण सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो सपा की विदाई सुनिश्चित है। कफ सिरप मामले पर कहा कि उन्होंने का की जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ब्रेनवेव साइंस एक्सपो 2025" का भव्य आयोजन किया गया

एस.आर. ग्लोबल स्कूल द्वारा बड़े गौरव के साथ वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शनी "ब्रेनवेव साइंस एक्सपो 2025" का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावक–शिक्षक बैठक भी संपन्न हुई। पूरा कार्यक्रम रचनात्मकता, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रभावशाली प्रदर्शन रहा। नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने 200 से अधिक विज्ञान मॉडलों का निर्माण कर अपनी वैज्ञानिक सोच, कल्पनाशीलता और शोध–दृष्टि का परिचय दिया। विद्यार्थियों ने अपने मॉडलों को आत्मविश्वासपूर्वक अभिभावकों एवं आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुत किया, जो सराहना का केंद्र बना। विद्यालय के अध्यक्ष एवं एम.एल.सी. श्री पवन सिंह चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों की प्रतिभा, नवाचार एवं उत्साह की भूरि–भूरि प्रशंसा की। उनके प्रेरणादायी संबोधन ने कार्यक्रम की गरिमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की। विज्ञान के साथ–साथ विद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग ने भी अपनी विशिष्ट रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।

विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत म्यूरल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स और विविध कलाकृतियों ने विद्यालय की समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा–दृष्टि को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया। आयोजित पी.टी.एम. ने अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धियों और आगे की शैक्षणिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा का अवसर प्रदान किया। ब्रेनवेव साइंस एक्सपो दृ 2025 ने न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता, समस्या–समाधान कौशल और सहभागिता की भावना को भी प्रबल किया।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है : इं रथिन सिन्हा

शाहजहांपुर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, भारत रत्न, कमजोर व उपेक्षित वर्ग के मसीहा परम् पूज्य बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के 70 वें परिनिर्वाण दिवस पर इं रथिन सिन्हा अधिशासी अभियंता, नि ख 1, लो.नि.वि शाहजहांपुर समेत विभागीय कर्मचारियों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी। बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इं रथिन सिन्हा ने कहा कि भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को प्रगति का विकल्प बताया है, बगैर शिक्षित हुए व्यक्ति कोई भी कार्य बेहतर तरीके से नही कर सकता है।बाबा साहब की देश के निर्माण में अतुलनीय भूमिका रही है। हम सबको उनके दिखाए हुए पर पथ पर चलना चाहिये तभी देश उन्नति करेगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता इं रथिन सिन्हा को बाबा साहब के जीवन पर आधारित भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जारी डाक टिकट प्रतिरूप प्रतीक चिन्ह डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के जनपद सचिव इं अहमद मुबीन ने भेंट किया। इस अवसर पर सहायक अभियंता इं महेंद्र कुमार, इं दिनेश सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष डिप्लोमा इंजी संघ इं राम औतार उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

ट्रेनों की धीमी रफ्तार में सक्रिय हो रहे गिरोह, निगरानी के दिए निर्देश

गोरखपुर, (संवाददाता)। ठंड बढ़ते ही आउटर और स्टेशनों के बीच ट्रेनों की धीमी गति का फायदा उठाकर यात्रियों के मोबाइल छीनने वाले गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हाल के दिनों में बढ़ी घटनाओं को देखते हुए एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन क्राइम मीटिंग में सभी थानेदारों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जहां–जहां ट्रेनों की स्पीड कम होती है, उन स्थानों पर पुलिस की निगरानी तत्काल बढ़ाई जाए। अपराधी अक्सर डंडे या लोहे की रॉड से हमला कर गेट पर खड़े यात्रियों का मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। ऐसे गैंग की पहचान कर उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसपी रेलवे ने जनपदीय पुलिस से समन्वय बनाकर संवेदनशील स्थानों पर पिकेट ड्यूटी लगाने और जेल से छूटे बदमाशों व हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बढ़ाने को कहा। मकर संक्रांति खिचड़ी मेला के दौरान रेलवे स्टेशन पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रात की गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

अमृत 2.0 के तहत विस्तारित क्षेत्र की महायोजना की तैयारी शुरू

गोरखपुर, (संवाददाता)। अमृत 2.0 योजना के तहत पीपीगंज नगर पंचायत और गोरखपुर महायोजना–2031 के शेष 177 वर्ग किमी अधिसूचित क्षेत्र की नई महायोजना तैयार होने जा रही है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग इस महायोजना को तैयार करेगा, जबकि इसके लिए आवश्यक सर्वे, मैपिंग और तकनीकी कार्यों का पूरा खर्च गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) वहन करेगा। प्राधिकरण बोर्ड की ओर से प्रति वर्ग किमी 18,000 रुपये की दर से भुगतान और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अभिकरण घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना की सब–स्कीम में 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों में पीपीगंज नगर पंचायत का चयन किया गया है। इसी क्रम में शासन ने जीडीए को एरिया ऑफ इंटरेस्ट (एओआई) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ ने व्यापक शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे प्राधिकरण क्षेत्र की महायोजना तैयार करने का सुझाव दिया है। 25 जुलाई 2024 को हुई बोर्ड बैठक में विस्तारित क्षेत्र की महायोजना को मंजूरी भी दी जा चुकी है। वर्ष 2020 की अधिसूचना के बाद पीपीगंज, मुंडेरा और पिपराइच नगर पंचायतों के साथ 233 राजस्व ग्रामों को जीडीए क्षेत्र में शामिल किया गया, जिससे प्राधिकरण का क्षेत्र बढ़कर लगभग 642 वर्ग किलोमीटर हो गया। पुनरीक्षित गोरखपुर महायोजना–2031 को शासन की स्वीकृति मिलने के बाद 7 मार्च 2024 से लागू किया गया है। इस 520 वर्ग किमी एओआई में से 465 वर्ग किमी क्षेत्र जीडीए के अधिकार क्षेत्र में शामिल है।

नशे के कारोबार में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं - रीता बहुगुणा जोशी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,06 दिसंबर। यूपी के जौनपुर में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने शनिवार को जौनपुर में खेलकूद एवं युवा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पैतृक आवास पर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। हिंदुस्थान समाचार से बात करते हुए कहा पश्चिम बंगाल के एक टीएमसी विधायक द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस पर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के प्रयास पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। जोशी ने कहा कि यह गलत हो रहा है और ऐसे प्रयासों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी हो और देश के कानून ने न्याय कर दिया हो, उस पर इस तरह का कार्य समाज को भड़काने और ध्रुवीकरण का प्रयास है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि संबंधित राज्य सरकार को इसे तत्काल रोकना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो इसे अदालत के माध्यम से रुकवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलत हो रहा है। मतदाता सूचियों में सुधार पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में न रहें। उन्होंने फर्जी नामों को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान पर, रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार ने 2026 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। सरकार ने इसे रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार और मोदी सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर जोशी ने स्पष्ट किया कि भाजपा जाति के आधार पर नहीं चलती, बल्कि यह देखती है कि कौन उपयोगी है और किसने निष्ठा से काम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं, वे सभी अच्छे रहे हैं और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा, वह भी अच्छा होगा। भाजपा नेताओं के नाम सामने आने पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ मोदी जी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

जीआरपी पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार

अयोध्या। जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को शनिवार को गिरफ्तार किया।पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से बैग मोबाइल फोन तथा कुछ नगद रुपए बरामद किए। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन समर बहादुर सिंह ने बताया कि उसे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पुराना माल गोदाम से गिरफ्तार किया गया।उसकी पहचान जितेन्द्र लोना उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र मंगरु लोना निवासी ग्राम सेमउरखानपुर थाना हंसवर जिला अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। पूछताछ में जितेन्द्र लोना बताया कि साढ़े तीन महीना पहले मैने रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम के प्लेटफार्म नं0 01 पर बैठे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी किया था।तथा करीब चार महिना पहले छपरा लखनऊ एक्सप्रेस में चलती ट्रेन के एसी डिब्बा से रेलवे स्टेशन अयोध्या कैण्ट के पास एक महिला के गले से उसका मंगलसूत्र और उसका बैग चोरी किया था।बैग में कुछ कपड़े व अन्य सामान थे जो मेरी जरुरत के नहीं समझ में आये।गिरफ्तार करने वाली टीम मे चन्द्रमणि पाण्डेय चौकी प्रभारी जीआरपी अयोध्या धाम जं0 थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट,उ0नि0 रामनारायण यादव थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट,का0 प्रशान्त कुमार सिंह थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट,का0 अवधेश यादव थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट शामिल रहे।

टैरिफ ने कालीन उद्योग से जुड़े दो लाख श्रमिकों का छीना रोजगार

भदोही, (संवाददाता)। अमेरिकी टैरिफ का असर कालीन कारोबार पर दिखने लगा है। टैरिफ से जिले में कालीन उद्योग से जुड़े करीब दो लाख श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। इसमें बुनकर, धुलाई, कताई और अन्य लोग शामिल हैं। एकमा के मानद सचिव पीयूष बरनवाल ने बताया कि इस साल कालीन निर्यात में कम से कम 35 फीसदी की गिरावट हो सकती है। टैरिफ का सीधा असर सूक्ष्म कारोबारियों पर पड़ा है। उनकी कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान के निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया है। इसके बाद से ही कालीन उद्योग में उथल–पुथल चल रहा है। टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही निर्यातक उद्योग को लेकर चिंतित थे। इस बीच कई दौर की वार्ता के बाद अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। कालीन पर टैरिफ लगे 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं। इससे उद्योग अब संकट में पड़ता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया कारपेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एकमा) के मानद सचिव पीयूष बरनवाल ने दावा किया कि टैरिफ के चलते भदोही में कालीन उद्योग से जुड़े दो लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसमें बुनाई करने वालों के साथ–साथ कताई, धुलाई और छंटाई, लेटेक्सिंग, डिजाइनिंग, डाईंग आदि करने वाले भी शामिल हैं। उद्योग पर पड़े असर के बीच महिलाओं के सामने भी संकट खड़ा हुआ है, जो महिलाएं घर का काम करने के बाद कताई, धुलाई या पेचाई जैसे काम करके अतिरिक्त आमदनी कर पाती थी। अब उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ कारण सूक्ष्म उद्यमियों ने कारोबार बंद कर दिया है। एक करोड़ तक सालाना कारोबार करने वाले 90 फीसदी कारोबारियों की कंपनियों में ताला लटक गया है। सूक्ष्म उद्यमी किसी तरह से बाजार में टिके हुए थे, लेकिन अचानक टैरिफ के झटके के कारण कई कंपनियां बंद हो चुकी है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के प्रशासनिक समिति के सदस्य पंकज बरनवाल ने बताया कि टैरिफ से अमेरिका के खरीदारों पर भी प्रभाव पड़ा है। अकेले अमेरिका के करीब 25 छोटे खरीदारों से कारोबार बंद हो चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बदले में उन्हें कुछ अच्छे और बड़े आयातक मिले हैं। बताया कि पिछले दिनों दो माह तक उनका करोड़ों का माल मुंबई पोर्ट पर डंप था। कोई खरीदार नहीं मिलने से अंततः उन्हें वहां से वापस मंगाकर भारी डिस्काउंट में बेचना पड़ा है। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका भारतीय कालीन कारोबार का करीब 60 फीसदी का हिस्सेदार है। पूंजी के अभाव में छोटे–छोटे भारतीय कारोबारी तो प्रभावित हैं ही, अमेरिका में भी छोटी कंपनियां जो भारतीय कालीन कंपनियों से हर साल हजारों करोड़ का कारोबार करती थी उनका कारोबार फिलहाल बंद हो चुका है। एकमा मानद सचिव, पीयूष बरनवाल ने बताया कि 2024–25 वित्तीय वर्ष में भारतीय कालीन ने रिकॉर्ड 17740 करोड़ का निर्यात किया था, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ मे ही अमेरिकी टैरिफ के लागू हो जाने से निर्यात में करीब 35 फीसदी की कमी आने की संभावना है। बताया कि इस साल पहली तिमाही में केवल 512 करोड़ का निर्यात हो सका है। निर्यात घटने से सीधा असर उद्योग और उससे जुड़े लोगों पर पड़ेगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।